यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

ए. के. बहल, ए. वी. एस. एम., पी. एच. एस. इत्यादि

(सिविल अपील संख्या 9382-83/2014)

24 जुलाई, 2015

[टी. एस. ठाकुर, आर. के. अग्रवाल और आदर्श कुमार गोयल, जेजे.]

सेवा कानूनः

कार्यकाल पद-निश्चित कार्यकाल-जैसा कि आदेश सं. 10 (14) 06/डी (मेड) दिनांक 20 अप्रैल, 2007 में दिया गया है-लेफ्टिनेंट जनरल और इसके समकक्ष के साथ-साथ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद के ए. एफ. एम. एस. अधिकारियों पर लागू-की संवैधानिक वैधता-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 20.4.2007 के आदेश द्वारा निर्धारित कार्यकाल का प्रिस्क्रिप्शन संविधान के अधिकार से बाहर था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अदालतों को सार्वजनिक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु के प्रिस्क्रिप्शन में हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए जब तक कि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन मनमाना और तर्कहीन न हो-कार्यकाल नियम इन शर्तों के अधीन बनाया गया था कि (i) अधिकारी यदि

60 वर्ष की आयु को छूने से पहले कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो वह 60 वर्ष की आयु को पूरा करने तक कार्यकाल से आगे जारी रह सकता है, (ii) अधिकारी को 61 वर्ष की आयु में पद छोड़ना होगा, भले ही उसने अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो-सशर्त कार्यकाल निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है-ऐसा कार्यकाल नियम बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में समान आधार पर लागू किया जा रहा है-सिर्फ इसलिए कि कुछ अधिकारियों को कुछ स्थितियों में 61 वर्ष तक की अनुमति दी जाती है, ऐसे अधिकारियों और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है-न्यायाधिकरण ने सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों में हस्तक्षेप करके सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने में गलती की थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:

1. अदालतों को सार्वजनिक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु के किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए जब तक कि निर्धारित आयु इतनी अनुचित रूप से कम न हो कि इसे मनमाना और तर्कहीन बना दिया जाए। [पैरा 11] (408-बी)

के. नागराज और अन्य आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1985 (2) एससीआर 579: (1985) 1 एससीसी523; टी. पी. जॉर्ज और अन्य बनाम द स्टेट ऑफ केरल और अन्य 1992 (2) एससीआर 311: 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 191; बी. भरत कुमार और अन्य बनाम उस्मानिया विश्वविद्यालय और अन्य। 2007 (6) एससीआर 168: (2007) 11 सेक्शन 58-पर निर्भर था।

2.1 सरकार लेफ्टिनेंट जनरलों और समकक्ष रैंक रखने वालों को कार्यकाल नियुक्ति के लिए वर्गीकृत कर सकती है। प्रत्येक पदाधिकारी को दो साल का कार्यकाल देने के लिए इस तरह का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय था। लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष के रूप में नियुक्त अधिकारियों के अनुभव, पेशेवर क्षमता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार अपने विवेक से निर्देश दे सकती है कि उस पद पर नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल दो साल का होगा। हालाँकि उस पर्चे ने एक विसंगति को जन्म दिया जहाँ एक अधिकारी जिसने अपेक्षाकृत कम उम्र में पद संभाला था, उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही घर जाना होगा। सरकार द्वारा 1 मई, 2000 के पत्र में संशोधन करके और कार्यकाल नियम को दो महत्वपूर्ण शर्तों के अधीन करके इसका निवारण किया गया था, अर्थात (i) यदि संबंधित अधिकारी 60 वर्ष की आयु को छूने से पहले दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो वह 60 वर्ष की आयु पूरी करने

तक उक्त कार्यकाल से आगे भी जारी रह सकता है। और (ii) एक अधिकारी 61 वर्ष की आयु में पद छोड़ देगा, भले ही उसने उस समय तक अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा न किया हो। [पैरा 13] (410-जी-डी; 411 ए-डी]

2.2 सशर्त रूप से दो साल के कार्यकाल को निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है, विशेष रूप से जब बिना शर्त प्रिस्क्रिप्शन के परिणामस्वरूप एक विसंगति हो गई थी, जहां एक अधिकारी जिसे अपनी योग्यता के कारण लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष का पद जीवन में जल्दी लेना पड़ता था, उसे उस रैंक में दो साल की अवधि पूरी करने के बाद, 60 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही बाहर जाना पड़ता था, जो संयोग से वह उम्र है जिस पर सेना और सेवाओं में अन्य समान रैंक सेवानिवृत्त होते हैं। इसी तरह, सरकार उन अधिकारियों के लिए एक ऊपरी आयु सीमा तय करने की हकदार थी जो जल्दी रैंक लेने में असमर्थ थे। उपर्युक्त दो शर्तों की शर्त से यह संकेत नहीं मिलता है कि सरकार ने ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष पद धारण करने वालों के लिए कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की कि लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष के पद पर सेवारत लोगों के लिए वास्तव में कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं था-कार्यकाल नियम सशर्त होने के कारण, इसे बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में

एक समान आधार पर लागू किया जा सकता है और किया जा रहा है। (पैरा 13,14) (411-डी-एफः 412-ए, सी-डी)

3. सिर्फ इसलिए कि लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष रैंक धारकों को कुछ स्थितियों में 61 वर्ष तक बने रहने की अनुमति है, ऐसे अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है जो 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। किसी भी तरह से, यह मानते हुए कि इसके लिए कोई कानूनी आधार है, शिकायत ऐसे अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जिन्हें 61 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जिन उत्तरदाताओं ने अपना दो वर्ष और 60 वर्ष की आयु का कार्यकाल पूरा कर लिया था, उनकी शिकायत गलत थी। न्यायाधिकरण ने सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति के आदेशों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। [पैरा 19) [419-ए-ई]

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम कैलाश चंद महाजन और अन्य 1992 (1) एस. सी. आर. 917:1992 अनुपूरक (2) एस. सी. सी. 351; नागालैंड के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य 2010 (7) एस. सी. आर. 630: (2010) 7 एस.

सी. सी. 643; यशवंत सिंह कोठारी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 1993 (1) एस. सी. आर. 208:1993 सप्लीमेंट (2) सेक्शन 592-पर निर्भर था।

डॉ. एल. पी. अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 (3) एससीआर 567: (1992) 3 एससीसी 526-विशिष्ट।

मामला विधि संदर्भ

1985 (2) एस. सी. आर. 579 में पर भरोसा किया गया। पैरा 11

1992 (2) एस. सी. आर. 311 में पर भरोसा किया गया। पैरा 12

2007 (6) एस. सी. आर. 168 में पर भरोसा किया गया। पैरा 12

1992 (1) एस. सी. आर. 917 में पर भरोसा किया गया। पैरा 15

2010 (7) एस. सी. आर. 630 में पर भरोसा किया गया। पैरा 16

1993 (1) एस. सी. आर. 208 में पर भरोसा किया गया। पैरा 17

1992 (3) एस. सी. आर. 567 विशिष्ट निर्दिष्ट। पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 9382-9383/2014

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के 2014 के 250 के ओ. ए. संख्या 250 और 2014 के ओ. ए. संख्या 296 में 2014 की ओ.

ए. संख्या 250 और 2014 की एम. ए. संख्या 541 में 12.09.2014 के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से रंजीत कुमार, एस. जी., बीनू टम्टा, आर. के. वर्मा, बी. वी. बलराम दास।

उत्तरदाताओं के लिए गोपाल सुब्रमण्यम, एस. जी., चिनमॉय शर्मा, आर. एन. करंजावाला, नंदिनी गोरे, अभिषेक रॉय, अदिति भट्ट, अमर दवे, बृजेश ओबेराय (करंजावाला एंड कंपनी के लिए)।

व्यक्तिगत रूप से कैविएटर

न्यायालय का निर्णय टी. एस. ठाकुर, जे. द्वारा

1. भारत संघ द्वारा दायर इन दो अपीलों में जो संक्षिप्त प्रश्न निर्धारित करने के लिए आता है, वह यह है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल और उसके समकक्ष रैंक के ए. एफ. एम. एस. अधिकारियों के साथ-साथ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक (डी. जी. ए. एफ. एम. एस.) के लिए लागू "कार्यकाल खंड" संवैधानिक रूप से मान्य है। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर ओ. ए. को अनुमति देते हुए यह विचार रखा है कि 20 अप्रैल, 2007 के आदेश No.10 (14)/06/डी. (मेड) में प्रदान की गई दो साल की एक निश्चित अवधि अधिकार से बाहर है और तदनुसार इस खंड को इस निर्देश के साथ अमान्य कर दिया है कि सभी लेफ्टिनेंट जनरल और ए.

एफ. एम. एस. में उनके समकक्ष उक्त आदेश में प्रदान की गई 61 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। विवाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न होता हैः

2. प्रतिवादी ए. के. बहल को 1 मार्च, 1976 को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन दिया गया था और उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर वायु सेना में नियुक्त किया गया था। उन्हें नियत समय पर पदोन्नत किया गया और 1 अप्रैल, 2012 को एयर मार्शल (लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष) के रूप में नियुक्त किया गया।। उनकी जन्म तिथि 17 सितंबर, 1954 होने के कारण, वह दो साल के कार्यकाल के बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30 सितंबर, 2014 को सेवानिवृत्त होने वाली मौजूदा नीति के प्रावधानों के तहत थे, जिसे उन्होंने 31 मार्च, 2014 को पूरा किया था।

3. संबंधित अपील में प्रतिवादी वाइस एडमिरल शैलेष रोहतगी, जिनकी जन्म तिथि 24 सितंबर, 1954 है, भी आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुए और उन्हें 1 जुलाई, 2012 को वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया गया जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद के बराबर है। उन्होंने 30 जून, 2014 को उस पद पर अपना दो साल का कार्यकाल पूरा किया और 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 30 सितंबर, 2014 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

4. 11 अक्टूबर, 2013 और 7 नवंबर, 2013 को प्रत्यर्थी एयर मार्शल ए. के. बहल को आदेश जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30 सितंबर, 2014 (ए. एन.) को सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। इसी तरह, 11 अक्टूबर, 2013 और 11 दिसंबर, 2013 के आदेश प्रत्यर्थी वाइस एडमिरल शैलेष रोहतगी को जारी किए गए थे।

5. पीड़ित, प्रत्यर्थियों ने वैधानिक शिकायतें प्रस्तुत कीं जिन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा "असमर्थनीय" के रूप में निपटाया गया था, इस आधार पर कि अधिकारियों को किसी भी सैन्य गलती के अधीन नहीं किया गया था और उन्हें सरकारी नीति के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जा रहा था जो ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष और डी. जी. ए. एफ. एम. एस. के रैंक के सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू था। उनकी वैधानिक शिकायत को खारिज करने के आदेश से नाराज, प्रतिवादी एयर मार्शल ए. के. बहल ने सशस्त्र बल अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष 2014 का ओ. ए. संख्या 250 दायर किया, जिसमें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की कार्यकाल से जुड़ी आयु निर्धारित करने और उन्हें जारी किए गए सेवानिवृत्ति आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना करने की सरकार की नीति को चुनौती दी गई। इसी तरह

की एक याचिका 2014 की ओ. ए. संख्या 296 प्रत्यर्थी वाइस एडमिरल शैलेष रोहतगी द्वारा भी दायर की गई थी। एयर मार्शल ए. के. बहल द्वारा दायर 2014 के ओ. ए. संख्या 250 को ए. एफ. टी. द्वारा अनुमति दिए गए एक आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 20 अप्रैल, 2007 के आक्षेपित आदेश No.10 (14)/06/डी/(मेड) में प्रदत्त दो साल का कार्यकाल खंड अधिकार से बाहर था और निर्देश दिया गया था कि ए. एफ. एम. एस. में सभी लेफ्टिनेंट जनरल और इसके समकक्ष रैंक धारक 61 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे। प्रतिवादी द्वारा अलग से स्पष्टीकरण के लिए दायर एक आवेदन पर, न्यायाधिकरण ने 15 सितंबर, 2014 का एक और आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि 11 अक्टूबर, 2013 और 7 नवंबर, 2013 के सेवानिवृत्ति के आदेश भी रद्द कर दिए जाएंगे। भारत संघ की ओर से अपील करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र के लिए की गई मौखिक प्रार्थना को न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, संघ ने अधिनियम की धारा 31 के तहत अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।

6. 15 सितंबर, 2014 के भारत संघ के चुनौती आदेश द्वारा दायर 2014 की सिविल अपील संख्या 9382-9383/2014 के O. A. No.296 में पारित की गई, जिसे प्रतिवादी वाइस एडमिरल शैलेष रोहतगी द्वारा 2014 के O. A. No.250 में अपने आदेश पर भरोसा करते हुए दायर किया गया

था। ठीक इसी तरह इन अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा।

7. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए, श्री रंजीत कुमार, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने की शक्ति पूरी तरह से सरकार के पास निहित है जिसके साथ न्यायाधिकरण गलती नहीं पा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि उपराज्यपालों और उनके समकक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार 1 मई, 2000 के पत्र के संदर्भ में निर्धारित किया गया था। हालाँकि, अनुभव से पता चला कि एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रचलित कार्यकाल खंड के कारण 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही सेवानिवृत्त हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि पदधारी ने कम उम्र में उस पद को संभाला था। ऐसी किसी भी विसंगति से बचने के लिए सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान को "किसी भी मामले में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नहीं" अभिव्यक्ति को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि मई, 2001 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सी. ओ. एस. सी.) से लेफ्टिनेंट जनरल के लिए निर्धारित कार्यकाल और ए. एफ. एम. एस. में इसके समकक्ष को हटाने की सिफारिश करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष बनाए रखने के प्रस्ताव की डी. ओ. पी. टी. द्वारा जांच की गई, जिन्होंने कहा कि कार्यकाल खंड

को हटाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु केवल 60 वर्ष ही रहेगी। कार्यकाल खंड को हटाते समय अधिकतम आयु 61 वर्ष बनाए रखना इस श्रेणी के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के समान पाया गया जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं था। सी. ओ. एस. सी. से लेफ्टिनेंट जनरल और 2 से 3 वर्ष के समकक्ष रैंक वाले अधिकारियों के लिए प्राप्त दूसरे प्रस्ताव पर भी डी. ओ. पी. टी. द्वारा विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया। इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरलों और उनके समकक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 1 मई, 2000 के पत्र में निर्धारित के अनुसार बनी रही, जैसा कि 20 अप्रैल, 2007 के पत्र द्वारा संशोधित किया गया था। श्री कुमार ने तर्क दिया कि अन्य सेवाओं के लिए लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है और कार्यकाल निर्धारित करने का उद्देश्य उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि प्रदान करना था, जो निश्चित रूप से 59 वर्ष या उससे अधिक आयु में उस पद को संभालने वाले अधिकारियों के मामले में 61 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अधीन था। श्री कुमार के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल और ए. एफ. एम. एस. में समकक्ष रैंक रखने वालों के लिए कार्यकाल प्रदान करने में सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों में कोई अवैधता या संवैधानिक दुर्बलता नहीं थी, बशर्ते कि यदि अधिकारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपना दो साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो वह

उस आयु तक बना रहेगा। जो अधिकारी 59 वर्ष या उससे अधिक आयु में पद ग्रहण करते हैं और दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में असमर्थ होते हैं, वे 61 वर्ष पूरा होने तक पद पर बने रह सकते हैं। इस तरह का प्रावधान पूरी तरह से उचित था और इसके परिणामस्वरूप 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दो वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने वाले और इसलिए सेवा से उचित रूप से सेवानिवृत्त होने वाले उत्तरदाताओं के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव या अन्य कोई भेदभाव नहीं हुआ।

8. प्रतिवादियों की ओर से न्यायाधिकरण के समक्ष और हमारे समक्ष भी दोहरे विवाद का आग्रह किया गया था। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि 20 अप्रैल, 2007 के पत्र द्वारा संशोधित 1 मई, 2000 के पत्र में ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर सेवारत लोगों की सेवानिवृत्ति के लिए दो तिथियां निर्धारित की गई हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, इसका तात्पर्य है कि दो साल का कार्यकाल खंड उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जो दो साल की सेवा पूरी करते हैं. लेकिन उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने तक सेवा में बने रहने की अनुमति है। इसी तरह जो लोग 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, वे भी 61 वर्ष पूरा होने तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तर्क यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल या ए. एफ. एम. एस. में इसके समकक्ष की सेवानिवृत्ति एक अनिवार्य कार्यकाल खंड द्वारा नियंत्रित नहीं होती है,

बल्कि सेवानिवृत्ति की आयु द्वारा नियंत्रित होती है जो लेफ्टिनेंट जनरल या इसके समकक्ष का पद संभालने वाले अधिकारियों की आयु के आधार पर 60 से 61 वर्ष के बीच भिन्न होगी। यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि मेधावी अधिकारी आम तौर पर पहले अपना पद संभाल लेते हैं, इसलिए वे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि कम मेधावी अधिकारी जो बाद में पद संभालते हैं, वे 61 वर्ष की अधिक आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, यह 'कार्यकाल नियुक्तियों' की अवधारणा के खिलाफ है, जिसका अर्थ है कि कार्यकाल एक पदधारी की नियुक्ति के साथ शुरू होता है और कार्यकाल की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल और ए. एफ. एम. एस. में समकक्ष रैंक में सेवारत अधिकारी, हालांकि, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रहेंगे, भले ही उनका दो साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, जिसका अर्थ है कि लेफ्टिनेंट जनरल का पद/रैंक एक गैर-कार्यकाल नियुक्ति है और विभिन्न सेवानिवृत्ति आयु द्वारा शासित है जिससे पूरा आधार मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण हो जाता है। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल का पद एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक पदोन्नति पद है। ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल के पद को कार्यकाल के पद के रूप में वर्णित करना, उत्तरदाताओं के अनुसार, एक गलत नाम है। विवादित कार्यकाल खंड, किसी भी दर पर, ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु के तहत लेफ्टिनेंट

जनरलों पर लागू होता है और एएफएमएस में इसके समकक्ष होता है और इसलिए, यह पूरी तरह से मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

9. इससे पहले कि हम निर्धारण के लिए आने वाले मुद्दे से संबंधित कानूनी स्थिति पर ध्यान दें, हम संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का उल्लेख कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर और ए. एफ. एम. एस. में समकक्ष सेवा करने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी आदेशों के संदर्भ में निर्धारित की गई है। 1 मई, 2000 के एक पत्र द्वारा सरकार ने पहले जारी किए गए आदेशों में संशोधन करते हुए ए. एम. सी. और डी. जी. ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरलों और समकक्ष के लिए सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की। पत्र में लिखा हैः

"सेवा में, 1 मई, 2000

डी. जी. ए. एम. एफ. एस.

विषय: लेफ्टिनेंट जनरल और सेना चिकित्सा कोर (ए. एम. सी.) के समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु।

महोदय,

मुझे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ओ. एम. संख्या 2501212197-पूर्व के अनुच्छेद 6 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। (ए) डी. ए. टी. ई. डी. 13.5.1988 और इस मंत्रालय का पत्र संख्या 14 (3)/डी. (ए. जी.) दिनांक 30.5.98 और 29.7.98 और 3.9.98 के साथ-साथ पत्र No.62212000/D (मेड) दिनांक 8.3.2000 और राष्ट्रपति की मंजूरी को व्यक्त करने के लिए कि सेना चिकित्सा कोर (ए. एम. सी.) के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित संशोधित सेवानिवृत्ति आयु/कार्यकाल होगा।

पद	सेवानिवृति की उम्र
ले. जनरल	2 वर्ष का कार्यकाल या 61 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो

डी जी ए एफ एम एस	3 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो।	

3. ये आदेश तुरंत लागू हो जाएंगे।

4. उन अधिकारियों की सेवा की अवधि जो इस मंत्रालय के पत्र संख्या 14 (3)/98/डी (एजी) दिनांक 30.5.98 और 29.7.98 के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति की मौजूदा आयु से परे सेवा में बने रहे हैं, उन्हें एक विशेष मामले के रूप में सेवा में विस्तार के रूप में नियमित किया जाएगा। ऐसे सभी अधिकारी 31.5.2000 से अपना पद छोड़ देंगे।

5. यह रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से जारी किया गया है। सं. 1254/एडीडीएल एफ. ए. (वी)/2000 दिनांक 1.5.2000।

भवदीय

xxxxxxxx

(जोस थॉमस)

भारत सरकार के अवर सचिव"

10. ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकाल खंड के लागू होने से श्री रंजीत कुमार द्वारा निर्दिष्ट विसंगति पैदा हुई है, जिससे सरकार के लिए 1 मई, 2000 के पत्र में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एक अधिकारी जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बना रहेगा। यह संशोधन 20 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा लाया गया था, जिसे विस्तार से भी निकाला जा सकता हैः

"सेवा में, नई दिल्ली 20 मई, 2007

डी. जी. ए. एम. एफ. एस.

विषय: सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (ए. एफ. एम. एस.) में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु।

महोदय,

मुझे रक्षा मंत्रालय में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी, पत्र संख्या 14 (3)/98-डी (एजी) दिनांक 1 मई, 2000 से निम्नलिखित रूप में सूचित करने का निर्देश दिया गया हैः

इसकी जगह

पद	सेवानिवृति की उम्र
ले. जनरल और समकक्ष (डीजीएएफएमएस के अलावा)	2 वर्ष का कार्यकाल या 61 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो
डीजीएएफएमएस	3 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो।

इसे पढ़ें

पद	सेवानिवृति की उम्र
ले. जनरल और समकक्ष (डीजीएएफएमएस के अलावा)	2 वर्ष का कार्यकाल या 61 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, लेकिन किसी भी मामले में 60 वर्ष की आयु प्राप्त

	करने से पहले नहीं।
डीजीएएफएमएस	3 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, लेकिन किसी भी मामले में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नहीं

2. इस विषय पर अन्य निर्देशों को तदनुसार संशोधित किया गया माना जाएगा।

3. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. यह रक्षा वित्त मंत्रालय की सहमति से उनकी डायरी संख्या 2483/अतिरिक्त एफ. ए. (एम) दिनांकित 19.4.2007 के माध्यम से जारी किया गया है।

भवदीय

xxxxxxxx

(आर सी रातूरी)

भारत सरकार के अवर सचिव"

11. के. नागराज और अन्य आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में (1985) 1 एस. सी. सी. 523 इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने लोक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु के अंतर्निहित प्रिस्क्रिप्शन के तर्क की जांच की और अदालतों को इस तरह के किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में हस्तक्षेप करने में संयम बरतने के लिए चेतावनी दी, जब तक कि निश्चित रूप से निर्धारित आयु इतनी अनुचित रूप से कम न हो कि इसे मनमाना और तर्कहीन बना दिया जाए। इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि लोक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए और यदि इसे निर्धारित किया जाता है तो इसे उचित के रूप में स्वीकार किया जाएगा जब तक कि निश्चित रूप से यह मनमाना या तर्कहीन होने के कारण पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं पाया जाता है। प्रधान न्यायाधीश के रूप में चंद्रचूड़ ने तब सार्वजनिक सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के अंतर्निहित तर्क और सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के लिए निर्धारित आयु को किसी भी चुनौती से निपटने में न्यायिक संयम की आवश्यकता को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। निर्णय का निम्नलिखित अंश शिक्षाप्रद हैः

"..... यह तथ्य कि सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में शर्त हमारी सभी सार्वजनिक सेवाओं की एक सामान्य विशेषता है, इसकी आवश्यकता को स्थापित करती है, कम से कम इसकी तर्कसंगतता सार्वजनिक हित की मांग है कि सार्वजनिक सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। दक्षता

के चरम स्तर का बिंदु व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होना तय है लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु स्पष्ट रूप से उस कारण से व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न नहीं हो सकती है। इसलिए कर्मचारियों के प्रदर्शन स्तरों के संबंध में अनुभव के आलोक में सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाली सामान्य अनुप्रयोग की एक सामान्य योजना विकसित की जानी चाहिए. समाज के युवा वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता और निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए उनके कैरियर की शुरुआत में पदोन्नति के अवसरों को अनिवार्य रूप से खोलने की आवश्यकता. लोक प्रशासक को सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करते समय परस्पर विरोधी दावों को संतुलित करना होगा। एक ओर सार्वजनिक सेवाओं को वरिष्ठ कर्मचारियों के परिपक्व अनुभव के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, दूसरी ओर सेवाओं के कनिष्ठ सदस्यों और समाज के युवा वर्गों के मन में हताशा और ठहराव की भावना पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। समाज के विभिन्न वर्गों के इन परस्पर विरोधी दावों के संतुलन में नीति के सूक्ष्म प्रश्न शामिल हैं जिन्हें जहां तक संभव हो कार्यपालिका और विधायिका के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इन दावों में अलग-अलग शक्ति और प्रयोज्यता के विचार शामिल हैं। अक्सर न्यायालय के पास यह तय करने के लिए कोई संतोषजनक और प्रभावी साधन नहीं होते हैं कि किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में कई प्रतिस्पर्धी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। हम यह सुझाव नहीं देते हैं कि

नीति का प्रत्येक प्रश्न न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है या आवश्यक रूप से, नीति के किसी भी और प्रत्येक प्रश्न की समीक्षा के लिए कोई प्रबंधनीय मानक नहीं हैं। यदि ऐसा होता, तो यह न्यायालय कारों से लेकर सरसों के तेल तक के व्यापक मूल्य निर्धारण विवादों पर विचार करने से इनकार कर देता। यदि सेवानिवृत्ति की आयु अनुचित रूप से निम्न स्तर पर निर्धारित की जाती है ताकि इसे मनमाना और तर्कहीन बनाया जा सके, तो न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, हालांकि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं, बल्कि मामले पर अधिक बारीकी से विचार करने के लिए। "जहाँ कोई अधिनियम मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।" (1974 [4] एस. सी. सी. 3) लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु जैसे नीतिगत मुद्दों की वैधता को हल करते समय, परस्पर विरोधी दावों को संवेदनशील न्यायिक पैमाने पर रखना और यह पता लगाकर मुद्दे का निर्णय करना उचित नहीं है कि संतुलन किस ओर झुकता है। यह एक ऐसी कवायद है जिसे प्रशासक और विधायिका को करना होता है। जैसा कि 'द सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशल फंक्शन' में कहा गया है [फिलिप्स बी. कुर्लैंड, ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिशिंग कंपनी, पृष्ठ 13 द्वारा संपादित]: "न्यायिक आत्म-संयम अपने आप में संतुलन प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले कारकों में से एक है, जो परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा महत्व रखता है।"

(महत्व दिया गया)

12. टी. पी. जॉर्ज और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रभाव का है। [1992 का उपबंध (3) एस. सी. सी. 191] जहाँ इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई थी, तब भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षकों को वास्तव में अपनी नौकरियों में निपुण होने से पहले कई वर्षों के शिक्षण अनुभव की आवश्यकता होती है, तब भी, सेवानिवृत्ति की सही आयु निर्धारित करना न्यायालयों के लिए नहीं है, बल्कि एक नीतिगत कार्य है जिसके लिए पर्याप्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जिसे केवल राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। उस अवलोकन के साथ न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करने और अपने विवेक में उपयुक्त मानी जाने वाली सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने का काम सरकार पर छोड़ दिया। बी. भरत कुमार और अन्य बनाम उस्मानिया विश्वविद्यालय और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है। (2007) 11 एस. सी. सी. 58 जहाँ इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"19 ..... यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह एक नीति तैयार करे कि सेवानिवृत्ति की आयु क्या होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से

हम विधायिका के विवेक के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे होंगे। यदि राज्य सरकार अपने विवेकाधिकार में, जो योजना के तहत उसके लिए अनुमत है, आयु को सीमित करने और इसे 60 तक बढ़ाने का निर्णय नहीं लेती है, या जैसा भी मामला हो, 62, तो ऐसा करना पूरी तरह से उचित था।

13. इस मामले पर आते हुए, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है और हमारी राय में, सही है ताकि सरकार लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष रैंक रखने वालों को कार्यकाल नियुक्ति के लिए वर्गीकृत कर सके। न्यायाधिकरण ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को दो-दो साल का कार्यकाल देने के लिए इस तरह का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य था। अन्यथा भी उस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष के रूप में नियुक्त अधिकारियों के अनुभव, पेशेवर क्षमता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार अपने विवेक से निर्देश दे सकती है कि उस पद पर नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल दो साल का होगा। हालाँकि उस पर्चे ने एक विसंगति को जन्म दिया जहाँ एक अधिकारी जिसने अपेक्षाकृत कम उम्र में पद संभाला था, उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही घर जाना होगा। सरकार द्वारा 1 मई, 2000 के पत्र में संशोधन करके और कार्यकाल नियम को दो महत्वपूर्ण शर्तों के अधीन करके इसका समाधान किया गया था, अर्थात (i) यदि संबंधित अधिकारी 60 वर्ष की आयु को छूने से पहले दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर

लेता है, तो वह 60 वर्ष की आयु को पूरा करने तक उक्त कार्यकाल से आगे चल सकता है। और (ii) एक अधिकारी 61 वर्ष की आयु में पद छोड़ देगा, भले ही उसने उस समय तक अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा न किया हो। सशर्त रूप से दो साल के कार्यकाल को निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है, विशेष रूप से जब बिना शर्त प्रिस्क्रिप्शन के परिणामस्वरूप एक विसंगति हो गई थी, जहां एक अधिकारी जिसे अपनी योग्यता के कारण लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष का पद जीवन में जल्दी लेना पड़ता था, उसे उस पद पर दो साल की अवधि पूरी करने के बाद, 60 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही बाहर जाना पड़ता था, जो संयोग से वह उम्र है जिस पर सेना और सेवाओं में अन्य समान रैंक सेवानिवृत्त होते हैं।

14. इसी तरह, सरकार उन अधिकारियों के लिए एक ऊपरी आयु सीमा तय करने की हकदार थी जो जल्दी रैंक लेने में असमर्थ थे। ऐसा करने का कारण स्पष्ट रूप से भारतीय सेना को वरिष्ठ पदों पर अपेक्षाकृत युवा रखने का सरकार का संकल्प था। कार्यकाल नियम यदि एक निर्बाध आवेदन की अनुमति देता है, तो हो सकता है कि उन लोगों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की आयु के आसपास रैंक लेने वालों की आयु 62 वर्ष हो गई हो। सरकार ने अपने विवेक से इस तरह के परिदृश्य को मंजूरी नहीं दी और कार्यकाल नियम को इस शर्त के अधीन कर दिया कि ए. एफ.

एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष का पद धारण करने वाले अधिकारी को 61 वर्ष की आयु में पद छोड़ना होगा, भले ही उसने अपना दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। उपर्युक्त दो शर्तों की शर्त से कम से कम यह संकेत नहीं मिलता है कि सरकार ने ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष पद धारण करने वालों के लिए कोई कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। यह इस तथ्य से काफी हद तक प्रदर्शित होता है कि मान लीजिए एक अधिकारी जो 58 1/2 वर्ष की आयु में अपना पद उठाता है, कि उसे 60 1/2 आयु के साथ अपना कार्यकाल पूरा करने पर पद छोड़ना होगा। वह पद पर बने रहने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि कार्यकाल नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि उन्हें दो साल का कार्यकाल पूरा करने पर या 61 साल पूरा करने पर "जो भी पहले हो" उन्हें पद छोड़ना होगा। इसलिए न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की कि वास्तव में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष के पद पर सेवारत लोगों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं था। यह कहना एक बात है कि एक अधिकारी दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी 60 साल की उम्र तक पद पर बना रहेगा, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि कोई कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल नियम सशर्त होने के कारण, इसे बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में एक समान आधार पर लागू किया जा सकता है और किया जा रहा है।

15. हम, इस स्तर पर, हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम कैलाश चंद महाजन और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। [1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 351] जिसमें कुछ हद तक विचार के लिए स्थिति उत्पन्न हुई। उस मामले में प्रतिवादी को शुरू में दो साल की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उस अवधि को समय-समय पर बिजली (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी की गई क्रमिक अधिसूचनाओं द्वारा बढ़ाया गया था। ऐसी अधिसूचनाओं में से अंतिम ने 25 जुलाई, 1989 से 25 जुलाई, 1992 को समाप्त होने वाली प्रतिवादी महाजन की नियुक्ति को तीन साल के लिए बढ़ा दिया। जनवरी, 1990 में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव हुए और राज्य में एक नई सरकार स्थापित हुई। 6 मार्च, 1990 को जारी एक अधिसूचना ने पहले जारी की गई अधिसूचना को हटा दिया और 25 जुलाई, 1989 से 6 मार्च, 1990 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। 6 मार्च, 1990 को जारी एक अन्य अधिसूचना में किसी और को 7 मार्च, 1990 से अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से व्यथित प्रतिवादी ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान 30 मार्च, 1990 को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें बोर्ड के सदस्य

के रूप में पहले प्रतिवादी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया था। इन दोनों अधिसूचनाओं को अंततः सरकार द्वारा वापस ले लिया गया और रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। लेकिन 11 जून, 1990 को प्रत्यर्थी को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया और अधिनियम की धारा 10 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की और एक अंतरिम आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी। इस स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव ने सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर एक अध्यादेश के माध्यम से बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद संभालने के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत सरकार ने राज्य को नियमों में संशोधन की व्यवहार्यता का पता लगाने की सलाह दी। इसके बाद सरकार ने बिजली (आपूर्ति) (एच. पी. संशोधन) अध्यादेश, 1990 जारी किया जो बाद में 1990 का अधिनियम 10 बन गया। इस प्रकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई थी। अध्यादेश और अधिनियम की अगली कड़ी के रूप में, प्रत्यर्थी को बताया गया कि वह 65 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने के बाद एच. पी. विद्युत बोर्ड का सदस्य और परिणामस्वरूप उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नहीं रह गया है। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उस कार्रवाई पर सवाल उठाया। इस न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा की गई अपील में एक दलील यह थी कि

राज्य किसी कार्यकाल के पदधारी के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करके पदधारी को बाहर नहीं कर सकता था। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य में कार्यकाल पद के लिए भी ऊपरी आयु सीमा निर्धारित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"हम प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से दिए गए तर्कों को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कार्यकाल के लिए कोई अवधि तय नहीं की जा सकती है। इस संबंध में उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, श्री शांति भूषण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 224 का सही संदर्भ दिया गया है, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया हैः-224. अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति-(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया के कारण, राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुछ समय के लिए बढ़ाई जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति विधिवत योग्य व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिए न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है जो दो वर्ष से अधिक नहीं है, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।

(2) जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने

पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति एक विधिवत योग्य व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर लेता है।

(3) उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति (बासठ वर्ष) की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

पुनः, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 8 का संदर्भ दिया जा सकता है। वह धारा इस प्रकार हैः-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन वह पांच साल की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगाः बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य

(ए) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में, 65 वर्ष की आयु 63 वर्ष और

(बी) किसी अन्य सदस्य के मामले में; 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा। इसलिए, जहां राज्य ने सदस्यों या विद्युत

बोर्ड के अध्यक्ष के लिए एक बाहरी आयु सीमा निर्धारित करने का नीतिगत निर्णय लिया है, वह पूरी तरह से कानूनी है।

16. नागालैंड में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य (2010) 7 धारा 643 यह न्यायालय इस बात की जांच कर रहा था कि क्या यह विहित करने वाला कोई प्रावधान कि कर्मचारी नागालैंड राज्य में 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे, जो भी पहले हो, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मनमाना, तर्कहीन या उल्लंघन था। अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि समान रूप से स्थित कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए एक अलग आधार निर्धारित करना भेदभावपूर्ण था। यह तर्क दिया गया था कि जो कर्मचारी 25 वर्ष से कम आयु में सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा, हालांकि वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, जबकि जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शामिल हुए थे, वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा जारी रख सकते हैं। कर्मचारियों के अनुसार, यह भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। कर्मचारियों की ओर से आग्रह किए गए विवाद का सार रिपोर्ट के निम्नलिखित अंश से एकत्र किया जा सकता हैः

"अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील श्री राम जेठमलानी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के माध्यम से सेवानिवृत्ति की अनुमति केवल उम्र के आधार पर है न कि सेवा की अवधि के आधार पर। तर्क यह है कि सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के माध्यम से सेवानिवृत्ति इस तरह की सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित एक विशेष आयु प्राप्त करने के कारण एक कर्मचारी के निर्वहन से संबंधित है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है। उन्होंने कहा कि जहां किसी भी सेवा में प्रवेश की न्यूनतम और अधिकतम आयु है, सेवा की अवधि के माध्यम से सेवानिवृत्ति की वैकल्पिक विधि के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से एक ही पद पर आसीन कर्मचारियों की सेवा में प्रवेश की आयु के आधार पर सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु होगी और इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का स्पष्ट उल्लंघन होगा; यह जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पदों के उन्मूलन के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा जारी रखने के एक स्थायी सरकारी कर्मचारी के मूल्यवान अधिकार के साथ भी असंगत होगा।

17. हालाँकि, इस अदालत ने यशवंत सिंह कोठारी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर [1993 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 592] में इस अदालत के

फैसले पर भरोसा करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"सार्वजनिक रोजगार से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति या 35 वर्ष की सेवा को पूरा करने का प्रावधान करने वाला आक्षेपित प्रावधान, जो भी पहले हो, स्पष्ट रूप से यशवंत सिंह कोठारी के मामले में निर्णय के अनुरूप है और उस मामले में अनुपात स्पष्ट रूप से हाथ में मामले पर लागू होता है। यदि 30 वर्ष की सक्रिय सेवा की अवधि लाभप्रद रोजगार के लिए एक छोटी अवधि नहीं थी, या 30 वर्ष से अधिक के पद पर रहने के अधिकार को रोकने के लिए एक मनमाना अभ्यास, 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, तो एक व्यक्ति को 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त किए बिना लोक सेवा से सेवानिवृत्त करना अनुचित या अस्वीकार्य नहीं माना जा सकता है।

आक्षेपित प्रावधान सेवानिवृत्ति के दो नियम निर्धारित करता है, एक उम्र के संदर्भ में और दूसरा सेवा की अधिकतम अवधि के संदर्भ में। वर्गीकरण वैध कारण पर आधारित है। विशेष रूप से, सेवा की अवधि में कोई एकरूपता नहीं रखी जा सकती है यदि सार्वजनिक रोजगार से सेवानिवृत्ति उम्र के कारण होती है क्योंकि सेवा में प्रवेश के समय सरकारी कर्मचारियों की आयु समान नहीं होगी। इसके विपरीत, आयु में कोई एकरूपता संभव नहीं हो सकती है यदि सेवानिवृत्ति नियम सेवा की

अधिकतम अवधि निर्धारित करता है। सेवा में प्रवेश के समय की आयु हमेशा इतना अंतर लाएगी। हमारे विचार में, उपरोक्त आधार पर आधारित आक्षेपित प्रावधान को चुनौती देने में विफल होना चाहिए।

18. यशवंत सिंह के मामले (उपरोक्त) में भी विनियमन ने सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के लिए एक दोहरा आधार निर्धारित किया है अर्थात 58 वर्ष की आयु प्राप्त करना या 30 वर्ष की सेवा पूरी करना, जो भी पहले हो। इस न्यायालय द्वारा नियम को चुनौती दी गई थी और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रावधान को बरकरार रखा गया थाः के. नागराज और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 551 में इस न्यायालय ने सरकार की नीति के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से घटाकर 55 करने की चुनौती को खारिज कर दिया, जो कि तर्कहीन या रोजगार योजना के मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन नहीं पाया गया। यह भी देखा गया कि सेवानिवृत्ति की आयु का प्रावधान नहीं करना सार्वजनिक हित के बिल्कुल विपरीत होगा क्योंकि राज्य अपने कर्मचारी को चरम सीमा पार करने के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति देने का खर्च वहन नहीं कर सकता है और सेवानिवृत्ति के नियम किसी सदस्य के आजीविका के अधिकार को नहीं छीनते हैं, एकमात्र सीमा उल्लिखित वर्षों तक पद पर बने रहने के अधिकार की है। पहले की तरह सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष बनाए रखने के लिए विनियमन में

प्रावधान है, लेकिन उसी अवधि में 30 वर्ष की सेवा के पूरा होने पर सेवानिवृत्ति की अनुमति, जो भी पहले हो, उस शिखर को प्राप्त करने वाले पद के वर्षों की एक निर्दिष्ट संख्या की गणना करने की नीति को ध्यान में रखते हुए है, जिसके बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति को उचित ठहराते हुए पतन होता है। इस संदर्भ में 30 वर्ष की सक्रिय सेवा की अवधि लाभप्रद रोजगार के लिए एक छोटी अवधि नहीं है, या 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने वाले तीस वर्ष से अधिक के पद पर रहने के अधिकार को रोकने के लिए एक मनमाना अभ्यास नहीं है।

19. उपरोक्त दो निर्णयों से जो पता चलता है वह यह है कि एक कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले वास्तव में कितने वर्षों का समय देता है या कर्मचारी की आयु सेवानिवृत्ति का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। एक दोहरा आधार हो सकता है, अर्थात् वह कितने वर्ष का कार्यकाल देता है और वह किस आयु में सेवानिवृत्त होगा। सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के लिए इस तरह के दोहरे आधार के अनुप्रयोग, कुछ स्थितियों में, जैसा कि नागालैंड के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के मामले (ऊपर) और यशवंत सिंह के मामले (ऊपर) में उल्लेख किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग उम्र में बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो नागालैंड के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के मामले (ऊपर) और यशवंत सिंह के मामले (ऊपर)

में लागू नियमों के तहत 20 वर्ष की आयु में शामिल होता है, उसे 35 वर्ष या 30 वर्ष पूरे होने के बाद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उसे 55 वर्ष की आयु में सेवा से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, जैसा कि नागालैंड के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के मामले (ऊपर) में और 50 वर्ष जैसा कि यशवंत सिंह के मामले (ऊपर) में है। इसके विपरीत, एक कर्मचारी जो 25 वर्ष की आयु में शामिल हुआ, वह 60 वर्ष की आयु तक सेवा करता रहेगा। सेवानिवृत्ति के लिए इस तरह के दोहरे आधार को मंजूरी देने वाले प्रावधानों को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया गया है, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि केवल इसलिए कि लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष रैंक धारकों को कुछ स्थितियों में 61 वर्ष तक बने रहने की अनुमति है, ऐसे अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है जो 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। कम से कम यह मानते हुए कि इसके लिए कोई कानूनी आधार है, शिकायत ऐसे अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जिन्हें 61 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वे शायद यह तर्क दे सकते हैं कि कार्यकाल के नियम को इस आवश्यकता से नियंत्रित या सशर्त नहीं किया जा सकता है कि पदधारी की आयु 61 वर्ष से अधिक न हो, हालांकि कलियाश चंद महाजन के मामले (ऊपर) में निर्णय उसी का एक पूर्ण उत्तर है। उन लोगों द्वारा ऐसी कोई

शिकायत नहीं की गई है जिन्हें केवल 61 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण कार्यकाल पूरा होने से पहले जाने के लिए कहा जाता है। जिन उत्तरदाताओं ने अपना दो वर्ष और 60 वर्ष की आयु का कार्यकाल पूरा कर लिया था, उनकी शिकायत इस दृष्टिकोण से गलत थी। ट्रिब्यूनल ने सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति के आदेशों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।

20. हम, अलग होने से पहले, डॉ. एल. पी. अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार कर सकते हैं। (1992) 3 एस. सी. सी. 526, जिसके आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा अपने इस निष्कर्ष के समर्थन में रखा गया है कि ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष का पद सावधिक पद नहीं हैं।

21. डॉ. अग्रवाल के मामले में (उपरोक्त) डॉ. अग्रवाल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के निदेशक के रूप में पांच साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। कार्यकाल के जारी रहने के दौरान, उन्हें नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर जनहित में सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था। उक्त आदेश को डॉ. अग्रवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका

को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि हटाने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। डॉ. अग्रवाल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर एक अपील में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि निदेशक का पद भर्ती नियमों के तहत एक सावधिक पद है, जिसमें उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था, इसलिए सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अवधारणा को लाकर कार्यकाल में कटौती नहीं की जा सकती है, जो अभिव्यक्ति एक सावधिक पद के लिए अलग थी। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि विनियमों के विनियम 30 (2) के प्रावधान के अनुसार, पदधारी के लिए 62 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की गई थी, फिर भी डॉ. अग्रवाल की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए थी, लेकिन नियुक्ति एक सावधिक पद नहीं रही। इस न्यायालय ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति का भी चयन किया जा सकता है और उसे निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी कर्मचारी को उसके कार्यकाल में कटौती करके समय से पहले नहीं हटाया जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवानिवृत्ति की अवधारणा डॉ. अग्रवाल के पक्ष में की गई नियुक्ति पर लागू होती है। डॉ. अग्रवाल के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय, हमारी राय में, उत्तरदाताओं की मदद नहीं करता है। वर्तमान में ऐसे मामले नहीं हैं जहां उत्तरदाताओं की सेवाओं को उस समय के दौरान समाप्त कर दिया गया है जब उत्तरदाता अपने दो साल के कार्यकाल का आनंद ले रहे

थे जैसा कि डॉ. अग्रवाल के मामले (उपरोक्त) में निर्णय था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां ए. एफ. एम. एस. में लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पार्श्व प्रविष्टि संभव थी। लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष के पद पर लागू कार्यकाल की अवधारणा की एकमात्र अतिरिक्त विशेषता यह है कि यदि अधिकारी जीवन में अपेक्षाकृत बाद में अपना पद संभालते हैं तो उनका कार्यकाल 61 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाएगा। डॉ. अग्रवाल के मामले (उपरोक्त) में जो स्थिति थी, उस मामले में लागू होने वाले विषय पर तथ्यात्मक मैट्रिक्स और नियम पूरी तरह से अलग हैं।

22. परिणामस्वरूप ये अपीलें सफल होती हैं, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादियों द्वारा दायर 2014 के ओ. ए. नंबर 296 और 2014 के 250 को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में बिना किसी आदेश के।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्कारण ही मान्य होगा।